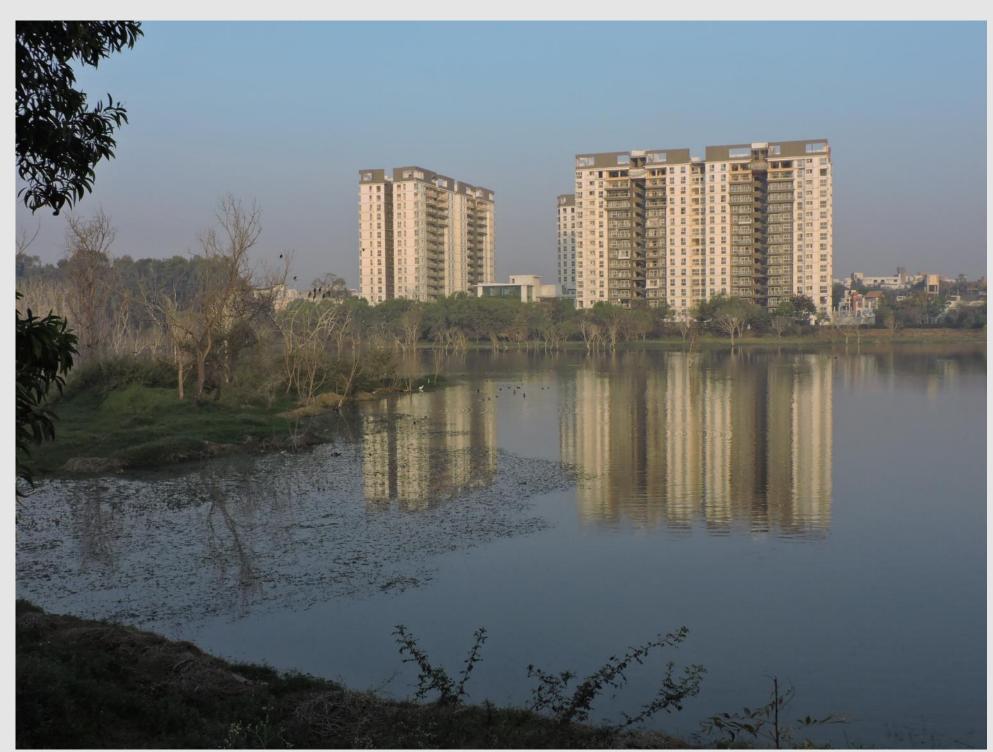
## शहरी टिकाऊपन या स्वावलंबन (जारी)



बेंगलूरू, कर्नाटक की काईकोंद्रहल्ली झील सामुदायिक सरगर्मियों के माध्यम से पुनर्जीवित की जा चुकी है।



रेनबो ड्राइव कॉलोनी, बंगलूरू में स्थित एक जल संचय टंकी।

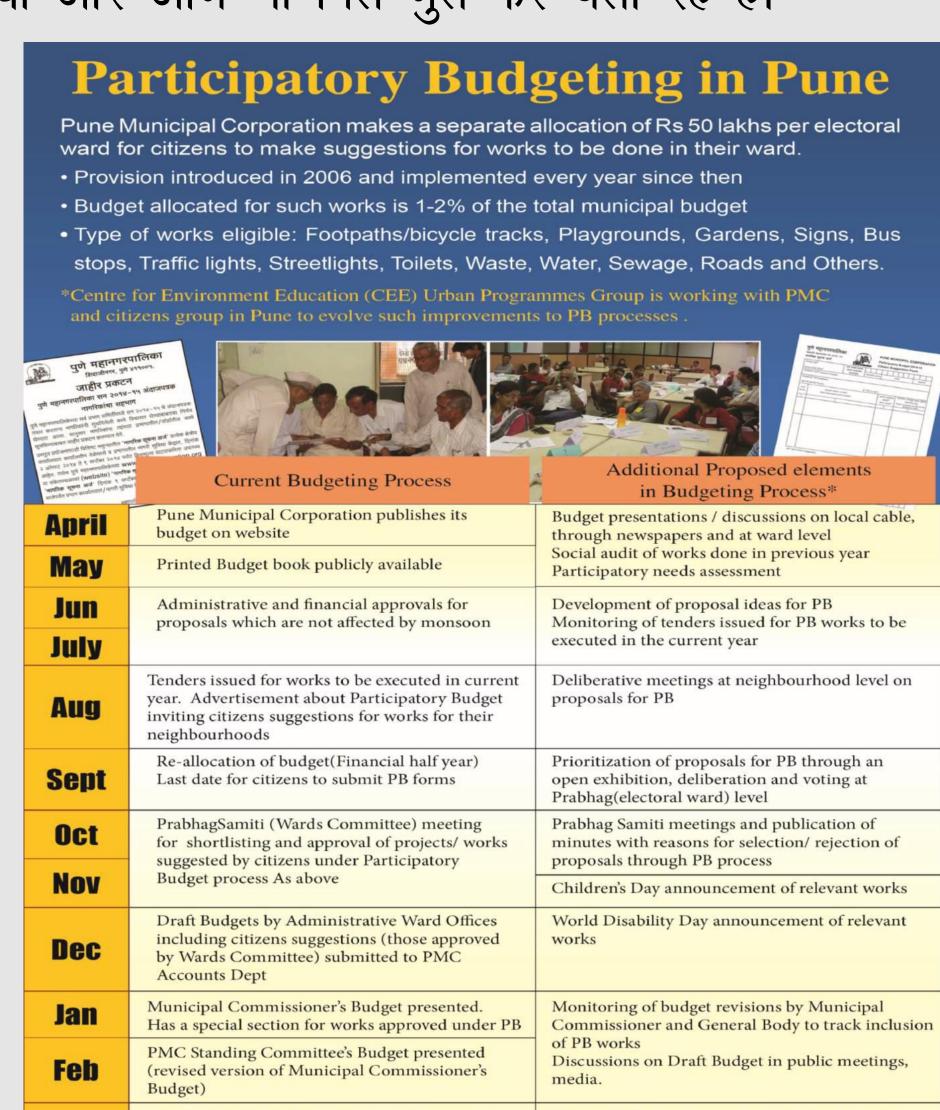
महाराष्ट्र स्थित पुणे शहर में बजट आवंटन की निर्णय प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण का एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है। यहां के नागरिकों ने ख़ुद यह तय करने का हक कुछ हद तक हासिल किया है कि टहलने और साइकिल चलाने, खेल के मैदान और बाग-बगीचे बनाने, कचरे और पानी का उपचार करने, बस स्टॉप्स बनाने, वृक्षारोपण करने आदि सहित कौन-कौन सी शहरी आवश्यकताओं पर कहां, कितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए।

सेंटर फॉर एनवायर्नमेंट एजुकेशन (सीईई) द्वारा जारी किए गए इस पोस्टर (दाएं) में सहभागी बजट की मासिक प्रक्रिया का ब्यौरा दिया गया

कुछ साल पहले तक बेंगलूरू शहर में स्थित काईकोंद्रहल्ली झील भी देश भर के शहरी जलाशयों के सामने पेश आ रही बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही थी। इनमें झील के किनारे पर खड़ी की जा रही इमारतों की घुसपैठ, झील में कचरा फेंकने और त्योहारों के दौरान धार्मिक सामग्री को पानी में प्रवाहित करने जैसी समस्याएं प्रमुख थीं।

मगर २००६ की शुरुआत में अलग-अलग पृष्ठभूमि वाले नागरिकों, निजी दाताओं और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर इस झील को पुनर्जीवित करने के लिए उसकी गाद की निकासी और धार्मिक गतिविधियों के लिए वैकल्पिक जलाशयों के बंदोबस्त जैसी गतिविधियां शुरू कीं। अब काईकोंद्रहल्ली आसपास के गांवों के लिए चारे का स्नोत है, शहरी सैलानियों के लिए सैर की जगह है और असंख्य पश्र-पिक्षयों के लिए बसेरा है। यह सफलता कभी झीलों के शहर के नाम से मशहूर रह चुके बेंगलुरू में जल संसाधनों की शृंखला को बहाल करने के एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

इस अभियान के तहत इस बात को मान्यता दी गई है कि झीलों के बचाव की कोशिशें सबसे पहले गंदे पानी और कचरे के उद्गम यानी हमारे घरों, बस्तियों और दफ्तरों से ही शुरू होनी चाहिए। फलस्वरूप, अब बेंगलूरू स्थित ३०० से ज्यादा परिवारों वाली रेनबो ड्राइव कॉलोनी के प्रत्येक घर में वर्षा जल का संचय किया जा रहा है, गंदे पानी का उपचार और रीसाइक्लिंग की जा रही है, गीले कचरे की कम्पोस्टिंग की जा रही है और ठोस कचरे की रीसाइक्लिंग की जा रही है। यह प्रयास खुद यहां के निवासियों ने शुरू किया था और आज भी मिल-ज़ुल कर चला रहे हैं।



Developed by Centre for Environment Education. November 2014

Women's Day announcement of relevant works

General Body of PMC debates and approves

the Budget accepted by Standing Committee

before 31st March

March